eradication of poverty as was in the case of Sixth Five Year Plan;

(b) whether in the light of the various rural and other economic programmes in the Sixth Five Year Plan, Government propose to redefine the term 'poverty line'; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI P. C. SETHI): (a) The main thrust of the Seventh Five Year Plan is on acceleration of the growth in foodgrains production, increase in employment opportunities and improvement of productivity, thereby reducing poverty and ensuring equity and social justice.

(b) and (c) The Planning Commission has constituted a Study Group on Cencepts and Estimation of Poverty Line. The Group has been entrusted with the job of examining the existing definition of 'Povetry line'. The deliberations of the Group are not over.

Enquiry into the Management of IISCO

1761. SHRI KALYAN ROY:
SHRI SANKAR PRASAD MITRA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply to the Unstarred Question 1929 on the 16th March, 1984 in the Rajya Sabha and state:

(a) whether the Committee which enquired into all the aspects of the management of IISCO has since submitted its report;

(b) if so, what are its findings and recommendations; and

(c) whether Government have taken any decision on this and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The report is being examined by the Government.

Contractors in Burnpur (IISCO) and Kulti Units

1762. SHRI KALYAN ROY:
SHRI SANKAR PRASAD MITRA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply to the Starred Question 289 on 12th March, 1979 in the Rajya Sabha and state:

(a) whether there has been any decline in the number of contractors in Burnpur (IISCO) and Kulti units and Jitpur and Chasnala units during the last four years and if so, what are the details thereof;

(b) what is the amont of money paid to each of the contractors in Burnpur, Kulti and other captive mines during the last three years till the end of July, 1984 and the details thereof, including the number of workers employed by each one of them; and

(c) what steps have been taken to reduce the number of contractors and payment to them and the details thereof including results of such actions taken so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) to (c) Requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनधिकृत रूप से भारतीय/विदेशी मुद्रा आदि रखने के लिए सरकारी पदाधिकारियों को दिए गए आरोप पत्र

1763. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या गृह मंत्री 26 जुलाई, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 441 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ दिल्ली में अपने घरों

में अनधिकृत रूप से भारतीय विदेशी मुद्रा, सोना और हीरे-जवाहरात रखने के सिलसिले में मामले दर्ज किए गए हैं ;

(ख) ये आरोप कानून के किन उपबंधों के अधीन लगाये गए हैं ;

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ये आरोप लगाये गए हैं, वे कौन कौन से विभागों में नियुक्त हैं और प्रत्येक विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। जैसा कि दिनांक 26-7-84 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के उत्तर में कहा गया था केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 3 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में दिल्ली में 78 सरकारी अधिकारियों के निवास-स्थानों पर छापा मारा गया था। दिल्ली में उनके निवास-स्थानों की तलाशी के दौरान, 6 मामलों में कुछ भारतीय/विदेशी मुद्रा और कुछ सोने के जेवरात जब्त कर लिए गए थे। इन 6 मामलों में से एक मामला विदेशी मुद्रा और एक मामला विदेशी मुद्रा तथा सोने के जेवरात दोनों से सम्बन्धित है तथा शेष 4 मामले भारतीय मुद्रा और/अथवा जेवरात जब्त किए जाने से सम्बन्धित हैं।

सरकारी कर्मचारियों के मामलों और उन विभागों के ब्यौरे जिनसे वे सम्बन्धित हैं, की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :—

क्रम सं०	कानून की धारा सं० के साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला	इसमें अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या	विभाग	वर्तमान स्थिति
1.	आर सी-4118 1-डी एल आई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 47 के 5(1)(घ) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/161 और 5(2) के अधीन।	1	स्वास्थ्य मंत्रालय	विचारण के लिए लम्बित है।
2.	आर सी-19/83-डी एल आई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 47 के 5(1)(घ) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 और 5(2) के अधीन।	1	संचार मंत्रालय	यथोचित

क्रम सं०	कानून की धारा सं० के साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला	इसमें अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या	विभाग	वर्तमान स्थिति
3.	आर सी-2/82-डी एल आई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के 5(1) (ङ) के साथ पठित 5(2) के अधीन।	1	दिल्ली प्रशासन	विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
4.	आर सी-1/81-डी एल आई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के 5(1)(ङ) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन।	1	उद्योग मंत्रालय	यथोपरि
5.	आर सी-21/83 डी एल आई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के 5(1)(ङ) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन।	1	रक्षा मंत्रालय	मामले की जांच चल रही है।
6.	आर सी-4/83 के ई आर भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947 के 5(1)(ङ) के साथ पठित 5(2) के अधीन।	1	वित्त मंत्रालय	यथोपरि

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 46 के अधीन जहां कोई पुलिस अधिकारी (सी०बी०आई० सहित) कोई विदेशी मुद्रा जब्त कर लेता है, वहां वह मुद्रा जब्त किए जाने की रिपोर्ट तुरन्त नजदीकी प्रवर्तन अधिकारी को देगा जो कि सहायक प्रवर्तन निदेशक के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। उपर्युक्त क्रम संख्या-1 पर दिए गए मामले के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के जब्त किए जाने की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी को दे दी गई है। उपर्युक्त क्रम संख्या 6 पर दिए गए मामले के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के जब्त किए जाने की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी को अभी तक नहीं दी गई है।

Special Provision for SC/ST in the Seventh Five Year Plan

1764. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details of all the special provisions to be made for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Seventh Five Year Plan;

(b) whether Government propose to give high priority for the social and economic development of the tribals; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c) The Paper on the Approach to the Seventh Five Year Plan (1985—90) has been